बढ़ते रकबे से जगी दालों में आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद

चालू सीजन में दलहन बोआई का रकबा 2.7 प्रतिशत बढ़कर 310 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा, कुल खपत का 25% होता है आयात

अरविंद शर्मा ● जागरण

- सरकार का वर्ष 2029 तक आयात पर निर्भरता खत्म करने का लक्ष्य
- सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है। लेकिन उत्पादन एवं खपत का अनुपात देखकर यह संभव नहीं लग रहा है। फिर भी सरकार का संकल्प एवं दाल की खेती की ओर किसानों के बढ़ते रुझान ने उम्मीद जगाई है। आयात को शून्य करने के लिए केंद्र ने छह वर्ष के अभियान की शुरुआत की है। बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रबंध किया है, जिससे तुअर, उड़द एवं मसूर की उपज बढ़ाने के लिए खरीद एवं भंडारण की व्यवस्था करनी है। लक्ष्य 2029 तक आयात पर निर्भरता खत्म करने का है।

कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक दशक में दलहन का उत्पादन 60 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सरकारी खरीद में भी 18 गुना वृद्धि हुई है। दलहन का उत्पादन 2014 के 171 लाख टन से बढ़कर 2024 में 270 लाख टन हो गया है। विपरीत मौसम के बावजूद इस वर्ष ढाई प्रतिशत ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। चालू सीजन में दलहन की बोआई का रकबा भी 2.7 प्रतिशत बढ़ा। 1951 में भारत में दलहन का रकबा 190 लाख हेक्टेयर ही था, जो अब बढ़कर 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। उत्पादन बढ़ने के बावजूद घरेलू खपत की लगभग 25 प्रतिशत के लिए आयात पर ही निर्भरता है।

सरकार का दावा है कि चना और मूंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकी है। तुअर, उड़द और मसूर का उत्पादन बढ़ाने पर काम करना है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित कर संसाधन देने होंगे। प्रथम चरण में अरहर, उड़द एवं मसूर की सारी उपज खरीदने का फैसला लिया गया है। पहले कुल पैदावार का सिर्फ 40 प्रतिशत ही बेचा जा सकता था। उन्नत एवं हाइब्रिड बीज की उपलब्धता सहज करनी होगी। आयात नीति अनुकूल बनानी होगी।

उत्पादकता में भारत काफी पीछे

दूसरे देशों की तुलना में भारत में दाल की उत्पादकता काफी कम है। कनाडा में एक हेक्टेयर में करीब 1,910 किलोग्राम और अमेरिका में 1,900 किलोग्राम दाल की उपज होती है। चीन भी प्रति हेक्टेयर 1,821 किलो दाल उपजा लेता है। मगर भारत में सिर्फ 700 किलोग्राम दाल का उत्पादन ही हो पाता है।

> आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार को सबसे पहले आयात नीति पर विचार करना चाहिए। कोई निर्णय अचानक लेने से नुकसान किसानों को होता है। आयात शुल्क लगाने-हटाने का निर्णय कम से कम तीन महीने पहले लेना चाहिए, ताकि किसान उसके हिसाब से फसल की बोआई कर सकें। पहले से जमा माल बेच सकें। अचानक शुल्क हटाने से किसान अपना उत्पाद सस्ती दर पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। कारोबारियों को भी नुकसान होता है।
>
> **-ज्ञानेश मिश्र**, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल

कम होती गई उपलब्धता

आजादी के बाद खाद्य सुरक्षा पर जोर था, जिससे गेहूं-धान की खेती को प्रोत्साहन मिला। 1950 में दलहन का रकबा गेहूं की तुलना में लगभग दोगुना था, लेकिन बड़ी आबादी को गेहूं-चावल उपलब्ध कराने के प्रयास में दलहन की फसलें पीछे छूटती गईं। एक समय ऐसा आया कि आयात पर निर्भर होना पड़ा। अब दलहन का रकबा एवं उत्पादन जितना बढ़ता है, उससे ज्यादा खाने वाले बढ़ जाते हैं। इससे प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता कम होती गई। 1951 में दाल की प्रति व्यक्ति सालाना खपत 22.1 किलो थी, जो अब 16 किलो रह गई। हालांकि बीच के वर्षों में पोषण के प्रति जागरूकता के चलते खपत के आंकड़े में सुधार हुआ है।